बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 80

सही और गलत!

वर्ष 2019 के आम चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों लेकिन यह कहना उचित होगा कि 36 दिन तक चली इस कवायद के बाद निर्वाचन आयोग का कद छोटा हुआ है। ये चुनाव आधिकारिक तौर पर निहायत अशिष्टता से भरे हुए थे और इस अवधि के दौरान सत्ताधारी दल और विपक्षी उम्मीदवारों द्वारा उल्लंघन के तमाम मामलों की शिकायत के बाद अब आयोग में आपसी असहमति सामने आ रही है। निर्वाचन आयुक्तों में से एक अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई वाली बैठकों से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनकी असहमति को दर्ज ही नहीं किया जा रहा। लवासा विवादों के केंद्र में रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव प्रचार के दौरान धर्म को बीच में लाने और बालाकोट हमले का जिक्र करने के पांच मामलों में क्लीनचिट दी। लवासा ने इन सभी अवसरों पर विरोध किया। आयोग के नियमों के मुताबिक बहुमत का निर्णय मान्य होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी दलील में कहा था कि अल्पमत का निर्णय रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला अर्द्ध न्यायिक निर्णयों में नहीं आता है।

यह नजरिया चुनाव आयोग के ध्येय की रक्षा भले ही करता हो लेकिन यह उसकी आत्मा के अनुरूप नहीं है। यह एक खुला प्रश्न है कि क्या उसे प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा के प्रसारण के लिए सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए थी जबकि अभी चुनाव प्रचार समाप्त ही हुआ था। अगर यह यात्रा प्रचार अभियान के दौरान हुई होती तो कोई मुद्दा नहीं बनता। यह बात भी आश्चर्य का सबब है कि उसने मोदी और ममता बनर्जी को बंगाल में पूरे दिन चुनाव प्रचार की अनुमति क्यों दी, इसके ठीक बाद उसने चुनावी हिंसा की निंदा करते हुए प्रचार की अवधि को ही कम कर दिया। हाल के वर्षों में सार्वजनिक बहस में आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं। यह कहना उचित होगा कि इससे पहले के चुनाव आयोग ने भी कोई बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं अर्जित की है। न ही उनसे निपटने वाले राजनीतिक प्रतिष्ठान ने ऐसा कुछ किया है। वर्ष 2009 का उदाहरण हमारे सामने है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी ने अपने सहयोगी नवीन चावला को हटाने की अनुशंसा की थी क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी के करीब माना जाता था। वर्ष 2002 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कहा था कि तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जे एम लिंगदोह ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद जल्दी चुनाव कराने की उनकी मांग इसलिए ठुकरा दी थी क्योंकि वह ईसाई थे। सन 1989 में निर्वाचन आयोग को तीन सदस्यीय इसलिए बनाया गया क्योंकि तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री ने कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता का परिचय दिया था। शास्त्री को उनके दौर में कुछ व्यापक चुनाव सुधार लाने के प्रयास के लिए भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था लेकिन 1993 में टीएन शेषन ने इसे दोबारा शुरू किया। उनकी स्वायत्तता ने तमाम राजनीतिक दलों को असहज कर दिया था। शास्त्री और शेषन दोनों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता के नए मानक तय किए। उस वक्त तक इसे एक अनुगामी संगठन की छवि हासिल थी लेकिन बाद में यह संस्थागत निष्पक्षता की मिसाल बन गया। यह प्रतिष्ठा 2000 के दशक में गायब होने लगी। इसकी कमजोरी का एक सिरा यह भी है कि यहां होने वाली नियुक्तियां वह कार्यपालिका करती है जिसकी निगरानी का काम आयोग के पास है। उस लिहाज से देखें तो लवासा ने सच बोलकर असाधारण साहस दिखाया है। यह दुखद है कि आयोग ने उनकी सुविचारित दृष्टि को नकार दिया है।

अजय मोहंती

अच्छे दिनों का आगमन और सरकार की भूमिका

अगर सरकार शांति कायम करने, तत्काल न्याय प्रदान करने और लागत कम करने में सहायता करे तो भारत तेजी से प्रगति कर सकता है। विस्तार से बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

वर्ष 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के दो संस्करण सार्वजनिक किए थे। एक छोटा और दूसरा बड़ा। मैंने छोटे संस्करण को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर सेव किया था। मुझे लगा कि चूंकि एक अलग सरकार का वादा किया गया था और कहा गया था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ अधिकतम शासन होगा, ऐसे में मैं देश में आ रहे बदलाव को दर्ज करना चाहता था। करीब छह महीने बाद मैंने उसे हटा दिया। मैंने ध्यान दिया कि केवल नेतृत्व में बदलाव आया है, सरकार के कामकाज में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं आया है।

निश्चित तौर पर बाद के वर्षों में हालात और खराब हुए। इस महीने के शुरुआती दो सप्ताह में हमें ऐसी सुर्खियां देखने को मिलीं, 'मारुति ने मांग में कमी के चलते तीसरे महीने भी उत्पादन घटाया।' '21 महीनों में पहली बार देश के औद्योगिक उत्पादन में कमी।' 'वित्त वर्ष 2019 में वृद्धि दर तीन वर्ष के निचले स्तर पर।' 'आईबीसी भी फंसे हुए कर्ज से संबंधित पुराने विफल कानूनों की राह पर' या फिर 'नरेंद्र मोदी की सबसे विशिष्ट आर्थिक नीतियां सबसे बुरी साबित हुईं।' आखिर गलती कहां हुई?

मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की घोषणा के एक वर्ष बाद लेखक और विचारक अरुण शौरी ने कहा था कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार में गाय को शामिल कर दिया जाए तो यह सरकार वैसी ही है। यह व्याख्या अद्भुत थी। संप्रग की दोनों सरकार की पहचान थी रोजगार गारंटी योजनाएं, सरकारी क्षेत्र की अनुत्पादक कंपनियों को लगातार समर्थन, सांठगांठ के साथ बुनियादी परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक इजाफा, आधार जैसी विवादास्पद योजना, राजकोषीय घाटे को छिपाने के लिए बजट में करामात, कर आतंक, किसानों के लिए लोकलुभावनवाद आदि। राजग सरकार में भी काफी कुछ ऐसा ही था।

भाजपानीत सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। 30 वर्ष के अंतराल के बाद किसी सरकार को बहुमत मिला था। यह अप्रत्याशित बहुमत रोजगार और विकास के लिए था। इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संप्रग की योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सरकार ने मुद्रा नामक ऋण योजना शुरू की। सरकारी क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किया गया, कोई सार्थक विनिवेश नहीं, जो थोड़ा बहुत हुआ भी वह बहुत सार्थक नहीं था। मिसाल के तौर पर ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को खरीदना और पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को खरीदना। सरकारी कंपनियों से लाभांश के रूप में हजारों करोड़ रुपये की राशि ली गई। उनमें से कई के पास तो वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। सरकारी बैंकों में स्वामित्व, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। करदाताओं की हजारों करोड़ रुपये की राशि इन बैंकों में डाली गई ताकि ये परिचालित होते रह सकें। सब्सिडी कम करने वाली परियोजना के बजाय आधार निगरानी करने का उपाय बन गया है। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की बात चुटकुला साबित हुई है।

वस्तु एवं सेवा कर तथा संप्रग सरकार द्वारा प्रस्तावित ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) मोदी सरकार के दो बड़े सुधार हैं। परंतु उच्च जीएसटी दरों और पुरातनपंथी नियमों ने कई तरह की समस्याएं पैदा कीं। नौकरशाही और दिक्कतदेह आईबीसी ढांचे ने यह तय कर दिया कि नई व्यवस्था भी पुराने दिवालिया कानूनों की ही गति को प्राप्त हो। सौदेबाजी, लंबी निष्क्रियता और अनसुलझे मामलों की लंबी सूची इसका उदाहरण बन गई।

अब से कुछ सप्ताह में नई सरकार कार्यभार संभाल लेगी। वह ढांचागत बदलाव लाने के लिए क्या कर सकती है? तकनीकी दुनिया में कहा जाता है कि किसी भी चीज को दस गुना अलग बनाया जाए तभी वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाती है। गरीबी में जी रहे लाखों भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें भी शासन में 10 गुना अंतर पैदा करना होगा। ऐसा करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों से कुछ अलग सोचना होगा। योजनाएं, सब्सिडी और कर बढ़ाकर इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। हमारे रुख में ढांचागत बदलाव आवश्यक है। सरकार को खुद काम करने के बजाय सेवा प्रदाता बनना होगा। ऐसा करके ही रुख में 10 गुना बदलाव लाया जा सकेगा।

हमें यह यकीन दिलाया गया है कि सरकार की नीतियां और उसके कदम ही हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर चाहे मामला कृषि ऋण का हो, रोजगार का, आवास का, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का या खराब बुनियादी ढांचे का। बहरहाल, अगर हम अधिक गहराई मे जाएं तो हमें पता चलेगा कि सरकार अपने आप में समस्या है, न कि हल। हर घोटाला या हर बेकार होने वाले व्यय की जड़ लाइसेंसिंग, सरकारी क्षेत्र, निविदा या अपारदर्शी व्यवस्था में निहित होती है। इनके लिए अकेले सरकार ही उत्तरदायी है।

सन 1950 और 1960 के दशक में एक वक्त था जब निजी पूंजी और कौशल दुर्लभ थे और सरकार को औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करनी पड़ती थीं। तब से अब तक सरकार ने अबाध गति से विस्तार किया है। इससे निजी उपक्रमों का विकास सीमित हुआ। सांठगांठ वाले पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के उभार के चलते कई प्रतिभावान भारतीयों ने देश से बाहर का रुख किया। इन हालात को बदलना होगा। सरकार को अपनी भूमिका कम करनी होगी। यह काफी अनुत्पादक और गैरजवाबदेह है। आज प्रतिभा, पूंजी और निजी संस्थानों की ताकत को लाभकारी और गैरलाभकारी, दोनों क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार शांति कायम करने, तत्काल न्याय प्रदान करने और लागत कम करने में सहायता करे तो भारत तेजी से प्रगति कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वे हरसंभव तरीके से अपना नजरिया सामने रख सकेंगे। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो सरकार को कम कर की आवश्यकता होगी। वह अपनी ऊर्जा वृद्धि को गति प्रदान करने में लगा सकती है। तब सही मायने में अच्छे दिन आएंगे।

भारतीय राज्य के स्वरूप में सुधार को देनी होगी तवज्जो

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

चुनावी कोलाहल के बीच में एक भीषण चक्रवाती तूफान का दस्तक देना अच्छी बात नहीं है। कुछ समय के लिए तूफान से जुड़ी बातें सुर्खियों में रहीं और इस दौरान राजनीति के भी बढ़िया मौके बने। मसलन, तूफानी विपदा से निपटने के लिए किसने अच्छा काम किया और किसने नहीं किया? लेकिन यह सच है कि फनी तूफान ने ओडिशा के बड़े हिस्से और पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में भी काफी नुकसान पहुंचाया। यह अपने पीछे टूटे घर, बिजली के गिरे खंभों और ढांचागत बरबादी के निशान छोड़ गया है। एक ही झटके में ओडिशा ने कई वर्षों के अर्जित विकास लाभांश को गंवा दिया है।

लेकिन इस तूफान के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या पहले से कम रहीं। इससे वैज्ञानिकों और ओडिशा के प्रशासन की तरफ से 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने और उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए अद्भुत प्रयासों का भी पता चलता है। इससे पहले 1999 में ओडिशा में आए पिछले भीषण चक्रवाती तूफान में करीब 10 हजार लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार 170 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार हवाएं चलने के बावजूद मृतकों की संख्या 70 तक ही सीमित रखने में कामयाबी मिली है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

हालांकि यह समझने की जरूरत है कि जलवायु को लेकर जोखिम भरी इस दुनिया में फनी तूफान का क्या मतलब है? जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जलवायु परिवर्तन की तरफ उंगलियां उठने लगती हैं। लेकिन केवल जलवायु परिवर्तन को ही ऐसी विपदाओं के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए?

संशयवादी इस तरफ इशारा करेंगे कि तूफानों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाने वाले ठोस आंकड़ों की कमी है। कुछ बदलाव आया है लेकिन इस फर्क को मापने वाले काल-आधारित पैमाना काफी नहीं है। विश्व मौसम-विज्ञान संगठन की जलवायु आकलन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक उत्तरी गोलार्द्ध में उठने वाले उष्ण-कटिबंधी तूफान एक साल पहले के 63 से बढ़कर 74 हो गए जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में दोनों साल 22 तूफान दर्ज किए गए। ऐसे में अगर आप अपने जोखिम पर यह दलील दे सकते हैं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। तूफान तो आएंगे और जाएंगे। इसके लिए जलवायु परिवर्तन को भला क्यों दोष दें?

सच तो यह है कि भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक इन तूफानों में बड़ा फासला है। तूफानों के बारे में अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि कुछ वर्षों में आईएमडी ने तूफानों के बारे में अनुमान लगाने के विज्ञान में खुद को काफी सिद्धहस्त कर लिया है लेकिन यह अब भी सीखने के दौर से गुजर रहा है ताकि तूफानों के उद्भव एवं प्रसार के बारे में अनुमान लगाने की तकनीक और पद्धति को बेहतर किया जा सके।

आईएमडी को वर्ष 2017 के आखिर में केरल के तटीय इलाकों में आए तूफान 'ओकची' ने पहला झटका दिया था। कई लोगों की जान लेने वाले और समुद्र में गए मछुआरों को संकट में डालने वाला यह तूफान छह घंटों के भीतर ही गहरे दबाव के क्षेत्र से चक्रवाती तूफान बन गया था। हमें यह अहसास होना चाहिए कि उस तूफान का पूर्वानुमान लगाने और समय से चेतावनी जारी करने में नाकाम रहना महज मानवीय गलती नहीं थी। इसकी वजह ऐसे चक्रवाती तूफान की असामान्य प्रकृति थी जिसे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इसने अपनी दिशा बदल ली और अनुमानों से एकदम अलग रफ्तार पकड़ ली और पहले कभी भी नहीं देखी गई गति से बढ़ते हुए अधिक प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया। वैज्ञानिकों ने उस तूफान की प्रकृति में बदलाव का एक कारण तो यह बताया कि समुद्र में बने बेहद गर्म क्षेत्र की वजह से तूफान की दिशा और रफ्तार बदल गई।

लेकिन इस बार आईएमडी इन बदलावों के लिए पहले से तैयार था। उसने ओकची तूफान से मिले कड़वे सबक को बखूबी सीखा था। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने अधिक परिष्कृत उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अपने पूर्वानुमान मॉडल को सुधारा। लेकिन परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि वर्ष 2017 में सीखा हुआ सबक भी इतनी जल्द पुराना हो गया है।

इस मामले में फनी तूफान ने देखते-ही-देखते प्रचंड से बेहद प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया और निर्धारित समय से पहले ही तटीय इलाकों तक पहुंच गया। यह इस तथ्य के बावजूद हुआ कि भारत में चक्रवात का अब काफी अच्छा पूर्वानुमान होने लगा है। जरा सोचिए कि इसका असली वक्त में क्या मतलब है? फनी को दोपहर के बाद ओडिशा के तट तक पहुंचना था और उसके पहले उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की चुनौती थी। लेकिन फनी ने सुबह के समय ही पूरी तीव्रता से दस्तक दे दी। हालांकि राज्य सरकार ने निर्धारित समय से पहले ही लोगों को सुरक्षित निकालकर अपनी बेहतर तैयारी का परिचय दिया।

फनी ने भीतरी इलाकों का रुख किया और भुवनेश्वर तक रफ्तार में किसी कमी के बगैर जा पहुंचा था। यह अपने आप में आश्चर्यजनक बात है क्योंकि किसी भी तूफान को तीव्रता बनाए रखने और भारी बारिश करने के लिए जमीनी इलाके में नमी की जरूरत होती है। इस बार यह तूफान भीषण गर्मी के समय आया है जबकि इस समय में किसी भी सूरत में समुद्री तूफान कभी नहीं आते हैं। यह भीतरी इलाकों में कैसे और क्यों पहुंचा? भविष्य में इस तरह का अनुमान कैसे लगाया जाना चाहिए?

फनी हमें कई बातें बताता है। पहला, हमें मौसम के विज्ञान और आपदा से तत्काल निपटने के लिए सरकार की क्षमता बढ़ाने में निवेश करना होगा। दूसरा, तूफानों की संख्या के आधार पर हम यह नतीजा नहीं निकाल सकते हैं कि दुनिया अधिक या कम सुरक्षित है। लेकिन सबसे अहम बात, यह हमें बताता है कि भविष्य अधिक जोखिम वाला है और अनुमानों से परे अप्रत्याशित है। इस हकीकत के प्रति जागरूक होने का वक्त आ गया है। अब समय नहीं गंवाया जा सकता है।

कानाफूसी

103 नाबाद

पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में 103 वर्ष के श्याम सरन नेगी ने अपना वोट डाला। सन 1951 के लोकसभा चुनाव से वोट डाल रहे नेगी ने 32वीं बार वोट डाला। उन्होंने हर बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कालपा गांव के मतदान केंद्र पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नेगी ने 16 बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। वह 13 विधानसभा चुनावों और दो क्षेत्रीय परिषद चुनावों में भी मतदान कर चुके हैं। स्थानीय प्रशासन ने उनको घर से मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था कराई जो करीब ही प्राथमिक विद्यालय में स्थित था। वहां उनका जमकर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 19 मई को समाप्त हो गया है। अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल आने लगे तथा चुनाव परिणाम 23 मई को आएंगे।

बड़ी जल्दी है भाई!

तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के समन्वयक ओ पनीरसेल्वम के बेटे ओ पी रवींद्रनाथ पिछले दिनों उस समय विवादों में घिर गए जब एक मंदिर में उनका नाम तेनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में उल्लिखित कर दिया गया। गौरतलब है कि अभी लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा नहीं हुई है। जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो मंदिर प्रबंधन हरकत में आया और आनन-फानन में सांसद शब्द को ढक दिया गया। बहरहाल तब तक पर्याप्त विवाद हो चुका था। इसे लेकर आरोप- प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। चुनाव आयोग पहले ही तेनी लोकसभा क्षेत्र के कुछ बूथ पर पुनर्मतदान की बात कह चुका था। कुमार भी तत्काल खुद को पाकसाफ बताने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। बाद में एक पुलिस कॉन्स्टेबल को इस घटना का दोषी बताया गया। वह एआईएडीएमके का समर्थक है और एक बार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे जयललिता की सफलता की कामना करते हुए उसने अपना सर तक मुंडवा लिया था।

आपका पक्ष

एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय

लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आने वाले हैं। इससे पहले मीडिया में आ रहे एग्जिट पोल के नतीजे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग-अलग मीडिया संस्थान मतदान के बाद सर्वे करके एग्जिट पोल करते हैं लेकिन कई बार इनके नतीजे चुनाव परिणाम से बिल्कुल उलट आते हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के अनुसार राजग को 230 से 275 सीट और कांग्रेस को 175 से 190 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद एग्जिट पोल गलत साबित हुए। राजग को 187 सीटें और संप्रग को 219 सीटें मिली थी। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाले राजग को एग्जिट पोल के अनुसार 183 से 289 सीटें मिलने का अनुमान गलत साबित हुआ। राजग ने

रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से 336 सीटें लाकर सरकार बनाई। इस बार भी चुनाव परिणाम से पहले कई न्यूज चैनलों पर अलग-अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जिससे जनता भ्रमित हो रही है। दर्शकों के बीच संदेह की स्थिति बन रही है कि कौन से सर्वे को सही मानें। इस वक्त करीब 10 से 12 राष्ट्रीय न्यूज चैनल अलग-अलग आंकड़े पेश

एग्जिट पोल के मुताबिक राजग को भारी बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है

कर रहे हैं जिसमें राजग के केंद्र में सरकार बनाने की बात तो की जा रही है लेकिन सीटों की संख्या तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगी जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते। यह 23 मई को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय रहे।

उद्देश्य कुमार, मणिपाल

पर्यावरणीय तथा अन्य समस्याएं

विश्व में तेजी से विकास के साथ ही पर्यावरणीय तथा अन्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय उष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग), जल संकट, घटते वन क्षेत्र, घटते जीव जंतु, बढ़ती आबादी आदि समस्याओं पर वैश्विक बैठकें होती रहती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। अमेरिका के 43 प्रतिशत लोग बेहद प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति दूसरे बेल्ट ऐंड रोड फोरम में साफ सुथरी ऊर्जा की बात करते हैं तो हैं लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन उनका देश करता है। देश की बात करें तो महाराष्ट्र में जल संकट दिन प्रति दिन गहराता जा रहा है लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि साफ हवा की कमी के कारण 10 लाख प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 102 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वैश्विक तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक शोध के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न केवल अधिक आपदाएं आ रही हैं बल्कि यह अमीर देश और गरीब देशों के बीच आर्थिक असमानता कम करने में बाधक बन रहा है। फरवरी 2019 तक दुनिया की आबादी 7.71 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत की जनसंख्या 1.19 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। देश में केवल 24.39 प्रतिशत भूमि वन से घिरी है। देश को 32 प्रतिशत वन क्षेत्र का आंकड़ा छूना है ताकि नैसर्गिक पर्यावरण में संतुलन बनाया जा सके।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।